भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.882
उत्तर देने की तारीख 07 फरवरी, 2024

हाई स्पीड नेटवर्क

882. श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र के रामटेक-नागपुर लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वाई-फाई और उच्च गति के अन्य नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क कार्य नहीं कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को केवल इसके कारण कई कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नेटवर्क की कमी के कारण पीओएस तंत्र काम नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप राशन का वितरण नहीं हो पाता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या रामटेक-नागपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में मोबाइल टावर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान रामटेक-नागपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए मोबाइल टावरों का जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ङ) देश में पिछले 10 वर्षों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है:

- बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) की कुल संख्या मार्च-2014 में 6.49 लाख से बढ़कर दिसंबर-2023 में 28.78 लाख हो गई है।
- मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या मार्च 2014 में 90.45 करोड़ से बढ़कर नवंबर 2023 में 115.41 करोड़ हो गई है।

- इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या मार्च-2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर जून-2023 में 89.58 करोड़ हो गई है।
- नवंबर 2023 तक देश के 6,44,131 गांवों में से (गांव के आकड़ें भारत के महारजिस्ट्रार के अनुसार) लगभग 6,17,150 गांव अर्थात 95.8% गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

देश में दूरसंचार कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

- लगभग 55 हजार गांवों में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 41,331 करोड़ रुपये के परिव्यय से कुल 41,160 मोबाइल टावरों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
- सभी बसे हुए गांवों को कनेक्ट करने के लिए 1.88 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से भारतनेट कार्यक्रम के दायरे का विस्तार किया गया है।

जिला/राज्य-वार कनेक्टिविटी से संबंधित विवरण दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

*****